464

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

राजबीर सेहरावत जे. के समक्ष,

गजब सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य उत्तरदाता

2018 का सी. आर. आर. संख्या .767

20 फरवरी, 2019

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-धारा 94-याचिकाकर्ता द्वारा उसे किशोर घोषित करने वाले आवेदन को निचली अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया-आयु का निर्धारण-आयोजित, अभियुक्त की आयु के रूप में बोर्ड/अदालत के मूल्यांकन को प्रधानता दी गई है-मूल्यांकन शारीरिक उपस्थिति से या यहां तक कि आयु और आरोपी की समझ का निर्णय करने के लिए बुनियादी प्रश्न रखने जैसे अन्य तरीकों से परीक्षा के आधार पर भी किया जा सकता है-संदेह के मामले में, स्कूल द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को ध्यान में रखा जाए-ये दो प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, फिर धारा 94 में उल्लिखित अतिरिक्त प्रमाण पत्रों को ध्यान में रखा जाए-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के अनुसार मैट्रिक प्रमाण पत्र को दी गई प्रधानता अब 2015 के अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं है। स्कूल, याचिकाकर्ता ने विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अलग-अलग जन्म तिथियां दी हैं-आयोजित, नीचे की अदालतों ने सरकारी में जन्म तिथि का मूल्य देकर कोई अवैधता नहीं की है। प्राथमिक विद्यालय-याचिका खारिज।

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि कानून के नए प्रावधानों के तहत, अभियुक्त की उम्र के बारे में बोर्ड/न्यायालय के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी गई है।यह मूल्यांकन शारीरिक उपस्थिति पर या यहां तक कि परीक्षा के आधार पर अन्य तरीके से किया जा सकता है जैसे कि आरोपी की उम्र और समझ का फैसला करने के लिए बुनियादी प्रश्न पूछना।किसी भी मामले में, यदि न्यायालय/बोर्ड के मन में कोई संदेह है, तो प्रावधान निर्धारित करता है कि यह स्कूल द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि है जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित है; जिसे पहली बार में विचार में लिया जाएगा।यदि ये दोनों प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुभाग में उल्लिखित अतिरिक्त प्रमाण पत्रों पर विचार किया जाना चाहिए।

इसलिए, स्कूल प्रमाण पत्र और

जसवीर सिंह और अन्य बनाम शविंदर सिंह और अन्य

465

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

अभियुक्त की वास्तविक आयु का निर्णय करने के लिए न्यायालय के पहले विचार के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र को बराबर रखा गया है ।यह अदालत/बोर्ड पर है कि वह अभियुक्त की जन्म तिथि पर अंतिम निर्णय ले, इन दस्तावेजों में से किसी एक को देखते हुए या अन्य उपस्थित परिस्थितियों के साथ, जो मामले के रिकॉर्ड में आ सकते हैं ।किसी भी तरह से, पुराने नियमों में मैट्रिक प्रमाणपत्र को दी गई प्रधानता का स्थान अब इसके लिए उपलब्ध नहीं है ।मैट्रिक प्रमाणपत्र को अब वह विशेष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है ।यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अभियुक्त की आयु के निर्धारण में मैट्रिक प्रमाणपत्र की प्रधानता पर जोर देने के लिए उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों और इस न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, हालाँकि इस न्यायालय ने पाया है कि वे सभी निर्णय उन मामलों के विशिष्ट तथ्यों पर अलग-अलग हैं ।उन सभी मामलों में, 2015 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किए गए अपराध शामिल थे ।इसलिए 2015 के नए अधिनियम की धारा 94 का दायरा उन मामलों में से किसी में भी विचाराधीन नहीं था ।इसलिए, उन निर्णयों को 2015 के अधिनियम के प्रवर्तन के बाद किए गए अपराधों से जुड़े मामलों के लिए उदाहरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है ।(पैरा 10) अभिनिर्धारित किया कि जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, नीचे दिए गए न्यायालयों ने याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 07.08.1996 निर्धारित करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय के अभिलेख को आधार अभिलेख के रूप में लिया है ।यह भी रिकॉर्ड में आया है कि सरकार छोड़ने के बाद । स्कूल, याचिकाकर्ता ने अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अलग-अलग जन्म तिथियां दी हैं; जो उसकी उम्र के अनुरूप भी नहीं पाई गई हैं ।इसलिए, नीचे दिए गए न्यायालयों ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दर्ज जन्म तिथि को अधिक महत्व देकर कोई अवैधता नहीं की है ।निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा याचिकाकर्ता की आयु का यह निर्धारण पूरी तरह से 2015 के अधिनियम की धारा 94 की बाद की भावना में है ।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार किशोर न्यायालय/बोर्ड/समिति द्वारा आयु निर्धारित की जाती है, जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है, तो उसे मुकदमे के उद्देश्य से आरोपी की मानी गई आयु के रूप में निर्धारित किया गया है ।वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित आयु को निचली अपीलीय अदालत ने भी बरकरार रखा है ।इसलिए, हालांकि, निचली न्यायालयों के साथ मतभेद करने का कोई आधार नहीं है, हालांकि, भले ही इस न्यायालय की याचिकाकर्ता की जन्म तिथि के बारे में कोई दूसरी राय थी; नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा निर्धारित एक से, यह पहली बार के न्यायालय की संतुष्टि के स्थान पर अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, जिसे क़ानून के तहत अभियुक्त की उम्र का अंतिम न्यायनिर्णायक बनाया गया है ।

(पैरा 12)

माना जाता है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है ।तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है ।

(पैरा 14)

अंकुर लाल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

एम. डी. शर्मा, ए. ए. जी, हरियाणा।

ऋतुराज सिंह, अधिवक्ता

गौतम दत्त के लिए-अधिवक्ता

शिकायतकर्ता के वकील,

राजबीर सहरावत, जे। (मौखिक)

(1) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 03.01.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई है; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 24.04.2017 के आदेश के खिलाफ एक अपील को खारिज करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उसे किशोर घोषित करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता पुलिस स्टेशन सदर बल्लभगढ़, फरीदाबाद में दर्ज प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 78 दिनांक 15.03 .2017 आई. पी. सी. की धारा 148,149,307,506,452 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत, दिनांक 15.03.2017 से उत्पन्न एक मामले में शामिल है ।आपराधिक कानून की पूरी कठोरता से बचने के लिए, याचिकाकर्ता ने उसे किशोर घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया था; यह दावा करते हुए कि अपराध करने के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी और इसलिए, उस पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

(3) याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा निर्णय लिया गया था और यह माना गया था कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को 07.08.1996 के रूप में लिया जाना है ।इसलिए, घटना की तारीख पर, याचिकाकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाती है ।इसलिए, याचिकाकर्ता किशोर नहीं था।

(4) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की ।हालांकि, निचली अपीलीय अदालत ने भी अपील को खारिज कर दिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। तदनुसार, यह आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता को एक वयस्क के रूप में लिया जाएगा न कि एक किशोर के रूप में।

(5) इस प्रकार निर्णय लेते समय, निचली न्यायालयों ने याचिकाकर्ता की जन्म तिथि पर भरोसा किया है जैसा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मुजेदी में उल्लेख किया गया है, जहाँ याचिकाकर्ता को पहली बार वर्ष 2002 में प्रथम श्रेणी में भर्ती कराया गया था और वहाँ उसकी जन्म तिथि 07.08.1996 के रूप में दर्ज की गई थी।

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

फाइल पर साक्षय पर विचार करते हुए, नीचे की अदालतों ने दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता ने साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फरीदाबाद में प्रथम श्रेणी में 24.08.2008 पर भर्ती होने का दावा किया है और वहां उसकी जन्म तिथि 26.08.2003 के रूप में दर्ज की गई थी ।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जारी स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बल्लभगढ़ में प्रवेश लिया था ।हालाँकि, गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लेते समय, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को एक बार फिर बदल दिया गया और इसे 23.07.1999 के रूप में उल्लेख किया गया ।याचिकाकर्ता ने यह स्कूल भी छोड़ दिया था और 10 वीं कक्षा में जय भारत स्कूल में प्रवेश लिया था ।गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जारी स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर, जय भारत स्कूल में दर्ज जन्म तिथि 23.07.1999 है। इसलिए, यह वह तारीख है जो मैट्रिक प्रमाणपत्र में आई है ।यदि याचिकाकर्ता की उम्र 23.07.1999 से गिना जाता है, तो वह अपराध करने की तारीख को किशोर है ।हालांकि, रिकॉर्ड, जैसा कि अदालत की फाइल में लाया गया है, से पता चलता है कि जन्म तिथि यानी 23.07.1999, जैसा कि गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जय भारत स्कूल में उल्लेख किया गया है, खुद साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उल्लिखित जन्म तिथि पर आधारित है, जहां इसे अलग-तरीके से 26.08.2003 के रूप में दर्ज किया गया है, नीचे दी गई अदालतों ने मैट्रिक प्रमाण पत्र पर विश्वास करने से इनकार कर दिया है। जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23.07.1999 है ।निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (संक्षेप में नियम) के अनुसार, नियम 12 ने उम्र के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित किया है, जहां एक आरोपी किशोर होने का दावा करता है ।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार, यदि उपलब्ध हो तो मैट्रिक प्रमाण पत्र को प्रधानता दी जानी चाहिए ।अन्य सामग्री, यानी स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब मैट्रिक प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो ।यदि स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो केवल नगर निगम या किसी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए ।इसलिए, वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि पहला प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक प्रमाण पत्र स्वयं उपलब्ध है, इसलिए, अन्य प्रमाण पत्रों को याचिकाकर्ता की आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार से बाहर रखा गया है, और मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि के अनुसार, याचिकाकर्ता एक किशोर है ।इसलिए, नीचे के दोनों न्यायालयों ने उपरोक्त नियम के प्रावधानों का पालन नहीं करके एक गंभीर अवैधता की है,

जबकि याचिकाकर्ता की आयु निर्धारित करना,याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक अन्य मामले में, उसी मैट्रिक प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता पर किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है।इस तथ्य को नीचे दिए गए न्यायालयों के ध्यान में लाया गया था।हालाँकि, इसे निचले न्यायालयों द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उन कार्यवाहियों में अन्य प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी।अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सिबा बिसोई बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

लोकनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम एम. पी. राज्य, पराग भाटी (किशोर) कानूनी अभिभावक-माता-श्रीमती रजनी भाटी के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य और डिवीजन बेंच का निर्णय इस न्यायालय ने विक्रम सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में फैसला सुनाया।(7) दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में अधिनियम) ने नियमों में निर्धारित पहले के प्रावधानों को हटा दिया है।अधिनियम में ही एक नया प्रावधान लागू किया गया है।उस प्रावधान के अनुसार, अभियुक्त की आयु निर्धारित करते समय मैट्रिक प्रमाण पत्र को अब प्रधानता का स्थान नहीं मिलता है।जहाँ तक उनके साक्षय मूल्य का संबंध है, स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक प्रमाण पत्र की तारीख को बराबर रखा गया है।यह अदालत पर छोड़ दिया गया है कि वह उसके सामने लाए गए व्यक्ति की उम्र का आकलन करे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (3) समिति/न्यायालय/बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु को मुकदमे के उद्देश्य से व्यक्ति की वास्तविक आयु बनाती है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सभी विद्यालयों में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि का अलग-अलग उल्लेख किया गया है।यहां तक कि मैट्रिक प्रमाण पत्र पर भी याचिकाकर्ता की जन्म तिथि होती है, जो आगे, जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पर आधारित होती है जो तीसरे पिछले स्कूल द्वारा दी गई थी।हालांकि, उक्त तीसरे पिछले स्कूल में प्रवेश रिकॉर्ड जन्म तिथि की पुष्टि नहीं करता है जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित है।इसलिए, निचले दोनों न्यायालयों ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है।

(8) विद्वान राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया है कि जांच एजेंसी ने मजिस्ट्रेट/

1 2017 (4) आर. सी. आर. के समक्ष सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं। (आपराधिक) 409

2 2017 आकाशवाणी (एससी) 3866

3 2012(4) आर. सी. आर (आपराधिक) 391

4 2016 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 1031

5 2017 (3) आर. सी. आर. (आपराधिक) ३०१

जसवीर सिंह और अन्य बनाम शविंदर सिंह और अन्य

469

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

याचिकाकर्ता की आयु के निर्धारण के समय बोर्ड ।सरकार में उल्लिखित निर्विवाद और प्रारंभिक जन्म तिथि। स्कूल रिकॉर्ड 07.08.1996 है ।इसलिए, न्यायालयों द्वारा याचिकाकर्ता की जन्म तिथि के रूप में इसे उचित रूप से लिया गया है ।याचिकाकर्ता के आवेदन को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है।

(9) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और कागजी पुस्तक को पढ़ने के बाद, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों में कोई सार नहीं मिलता है ।यद्यपि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 ने मैट्रिक प्रमाणपत्र को प्रधानता दी थी, लेकिन अभियुक्त की जन्म तिथि के अन्य प्रमाणों की तुलना में, उस प्रावधान को अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।एक नया प्रावधान अब अभियुक्त की आयु निर्धारित करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है ।अधिनियम की धारा 94 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"94. आयु का अनुमान और निर्धारण-(1) जहाँ,

समिति या बोर्ड के लिए यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्षय देने के उद्देश्य के अलावा) उसके सामने लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, समिति या बोर्ड बच्चे की उम्र को लगभग बताते हुए ऐसा अवलोकन दर्ज करेगा और उम्र की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 14 या धारा 36 के तहत जांच के साथ आगे बढ़ेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, साक्षय प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा।

(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में; (ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) और केवल (i) और (ii) के उपरोक्त की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसी आयु निर्धारण परीक्षा ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा अभिलिखित आयु उस व्यक्ति की आयु होगी जिसे उसके समक्ष इस प्रकार लाया गया है, इस उद्देश्य या इस अधिनियम के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

(10) अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि कानून के नए प्रावधानों के तहत, अभियुक्त की उम्र के बारे में बोर्ड/न्यायालय के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी गई है।यह मूल्यांकन शारीरिक बनावट पर या यहां तक कि अन्य विधि द्वारा परीक्षा के आधार पर भी किया जा सकता है जैसे कि आरोपी की उम्र और समझ का निर्णय लेने के लिए बुनियादी प्रश्न पूछना। किसी भी मामले में, यदि न्यायालय/बोर्ड के मन में कोई संदेह है, तो प्रावधान निर्धारित करता है कि यह स्कूल द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि है; जिसे पहली बार में ध्यान में रखा जाएगा।यदि ये दोनों प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुभाग में उल्लिखित अतिरिक्त प्रमाण पत्रों पर विचार किया जाना चाहिए।इसलिए, अभियुक्त की वास्तविक आयु का निर्णय करने के लिए न्यायालय के पहले विचार के लिए स्कूल प्रमाण पत्र और मैट्रिक प्रमाण पत्र को बराबर रखा गया है।यह अदालत/बोर्ड पर है कि वह अभियुक्त की जन्म तिथि पर अंतिम निर्णय ले, इन दस्तावेजों में से किसी एक को देखते हुए या अन्य उपस्थित परिस्थितियों के साथ, जो मामले के रिकॉर्ड में आ सकते हैं।किसी भी तरह से, पुराने नियमों में मैट्रिक प्रमाणपत्र को दी गई प्रधानता का स्थान अब इसके लिए उपलब्ध नहीं है। मैट्रिक प्रमाणपत्र को अब वह विशेष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अभियुक्त की आयु के निर्धारण में मैट्रिक प्रमाणपत्र की प्रधानता पर जोर देने के लिए उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों और इस न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, हालाँकि अभियुक्त की आयु के निर्धारण में दसवीं के प्रमाण पत्र की प्रधानता पर जोर देने के लिए इस न्यायालय ने पाया है कि वे सभी निर्णय उन मामलों के विशिष्ट तथ्यों पर अलग-अलग हैं।उन सभी मामलों में, 2015 के अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किए गए अपराध शामिल थे।इसलिए 2015 के नए अधिनियम की धारा 94 का दायरा उन मामलों में से किसी में भी विचाराधीन नहीं था।इसलिए, उन निर्णयों को 2015 के अधिनियम के प्रवर्तन के बाद किए गए अपराधों से जुड़े मामलों के लिए उदाहरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

(11) जैसा कि यह इस मामले के रिकॉर्ड में आया है, याचिकाकर्ता को पहली बार 02.08.2002 पर पहली कक्षा में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया गया था।उस समय, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 07.08.1996 के रूप में उल्लिखित थी।हालाँकि, याचिकाकर्ता का नाम

उसकी लगातार अनुपस्थिति के कारण उस स्कूल से बाहर हो गया।इसके बाद, अभिलेख पर लाए गए साक्षय से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने साई वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 24.08.2008 पर फिर से प्रथम श्रेणी में प्रवेश लिया था।वहाँ इस विद्यालय में उल्लिखित जन्म तिथि; प्रवेश के समय 26.08.2003 है।इस तथ्य को स्कूल के क्लर्क सी. डब्ल्यू. 4 ने भी उजागर कर दिया है।कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने स्कूल में 8 वीं कक्षा तक पढ़ाई की है।इसके बाद, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9 वीं कक्षा में प्रवेश लिया है; 10.07.2014 पर; साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जारी स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर, और इस स्कूल में प्रवेश के समय, उल्लिखित जन्म तिथि को फिर से 23.07.1999 में बदल दिया जाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल

में दर्ज जन्म तिथि में असमानता को समझाने की कोशिश की है कि साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जारी 8 पास प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि 23.07.1999 है, इसलिए, गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने इस तारीख को याचिकाकर्ता की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया था। हालाँकि, यह अपने आप में एक संदेह पैदा करता है।कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम श्रेणी में 24.08.2008 पर साई वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लिया था।इसलिए, उन्होंने केवल वर्ष 2016 में 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण की होगी, जबकि उन्होंने वर्ष 2014 में 9 वीं कक्षा में प्रवेश लिया है।यह स्वयं साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्कूल रिकॉर्ड में पूरे हेरफेर को दर्शाता है, जो गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9 वीं कक्षा में प्रवेश पाने के उद्देश्य से किया गया था। यह स्पष्ट है कि साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जन्म तिथि को जानबूझकर बदल दिया गया था और याचिकाकर्ता को उस स्कूल के रिकॉर्ड के विपरीत, जन्म तिथि को 26.8.2003 से 27.3.1999 में बदलकर, एक अलग जन्म तिथि के साथ 8 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र दिए गए थे।कहने की जरूरत नहीं है कि अगले साल फिर से याचिकाकर्ता ने स्कूल बदल दिया था और जय भारत स्कूल में प्रवेश लिया था, जहाँ से उसने मैट्रिक पास किया था।तदनुसार, याचिकाकर्ता के मैट्रिक प्रमाणन में उल्लिखित जन्म तिथि 23.07.1999 है; जैसा कि गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा प्रदान किया गया था।हालाँकि, चूंकि साई सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गंगोत्री मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा प्रदान की गई जन्म तिथि में ही हेरफेर किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के मैट्रिक प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के विश्वसनीय प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

(12) जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, निचले न्यायालयों ने याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 07.08.1996 निर्धारित करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय के रिकॉर्ड को आधार रिकॉर्ड के रूप में लिया है।इसमें भी

रिकॉर्ड पर आएं कि सरकार छोड़ने के बाद। स्कूल, याचिकाकर्ता ने अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अलग-अलग जन्म तिथियां दी हैं; जो उसकी उम्र के अनुरूप भी नहीं पाई गई हैं।इसलिए, निचले न्यायालयों ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दर्ज जन्म तिथि को अधिक महत्व देकर कोई अवैधता नहीं की है। निचले न्यायालयों द्वारा याचिकाकर्ता की आयु का यह निर्धारण पूरी तरह से 2015 के अधिनियम की धारा 94 की बाद की भावना में है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार किशोर न्यायालय/बोर्ड/समिति द्वारा आयु निर्धारित की जाती है, जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है, तो उसे मुकदमे के उद्देश्य से आरोपी की मानी गई आयु के रूप में निर्धारित किया गया है।वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित आयु को निचली अपीलीय अदालत ने भी बरकरार रखा है।इसलिए, हालांकि, नीचे दिए गए न्यायालयों के साथ मतभेद करने का कोई आधार नहीं है, हालांकि, भले ही इस न्यायालय की याचिकाकर्ता की जन्म तिथि के बारे में कोई दूसरी राय थी; निचले न्यायालय द्वारा निर्धारित एक से, यह पहली बार के न्यायालय की संतुष्टि के स्थान पर अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, जिसे क़ानून के तहत अभियुक्त की उम्र का अंतिम न्यायनिर्णायक बनाया गया है।

(13) यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अन्य मुकदमे में, याचिकाकर्ता पर एक किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है, हालाँकि, इस मामले के रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं आया है कि उस मामले में बोर्ड/अदालत द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित जांच की प्रक्रिया का पालन करके उसकी उम्र निर्धारित की गई थी। वास्तव में, उस मामले में, अभियोजन पक्ष ने स्वयं याचिकाकर्ता को किशोर के रूप में लिया था।यह भी स्वीकार किया जाता है कि कोई जांच नहीं की गई थी।याचिकाकर्ता की वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए उस मामले में कोई सबूत नहीं दिया गया था।इसलिए, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता पर एक अन्य मामले में किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा है, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की उम्र के निर्धारण के लिए एक प्रासंगिक कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया है।तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है।

(एंजेल शर्मा)

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंजू रानी

अनुवादक